www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 18 | जौनपुर, मंगलवार, 01 सितम्बर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात घटकर 900 पहुंचा, विधानसभा में आंकड़े पेश

हरियाणा , (एजेंसी)। हरियाणा में जून 2026 तक जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) 900 दर्ज किया गया है, जबकि पिछले पूरे वर्ष और 2019 में यह 923 था। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। हरियाणा विधानसभा को सोमवार को कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला के एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से 22 जिलों के लिए पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 2019 में 923 था जो घटकर जून 2026 तक 900 हो गया। कांग्रेस सदस्य ने कई मुद्दों के साथ–साथ यह भी जानना चाहा कि 2019 से हर साल राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात क्या रहा है और जिलेवार आंकड़े क्या हैं। विधायक ने पूछा कि क्या यह सच है कि 2019 के बाद से ज़्यादातर सालों में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट आई है? अगर ऐसा है, तो सरकार इस गिरावट को रोकने और स्थिति को सुधारने के लिए क्या खास कदम उठा रही है? सदन में पेश किए गए लिखित जवाब में, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े प्रस्तुत किए। आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 2019 में 923 से घटकर जून 2026 तक 900 रह गया है। आंकड़ों के मुताबिक कुछ जिलों में स्थिति अधिक चिंताजनक है।

मुंबई के कूपर अस्पताल में बुर्का पहनकर पहुंचीं महिलाओं को प्रवेश से रोकने पर विवाद

महाराष्ट्र, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा संचालित कूपर अस्पताल में बुर्का पहने दो महिलाओं को प्रवेश से कथित तौर पर रोके जाने का मामला सामने आया है। सोमवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए एक वीडियो में महिलाओं को सुरक्षा कर्मियों से बहस करते हुए देखा जा सकता है। अधिवक्ता जहरा शेख और उनकी एक मित्र किसी रिश्तेदार से मिलने अस्पताल पहुंची थीं, जहां उन्हें प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया। वीडियो में शेख अस्पताल परिसर में प्रवेश की कथित तौर पर अनुमति देने से पहले बुर्का उतारने की मांग का कड़ा विरोध करती नजर आ रही हैं। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की इस कथित मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे उनकी गरिमा और निजता प्रभावित होती है तथा यह धार्मिक स्वतंत्रता के उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। शेख के साथ मौजूद एक व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया। सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल के प्रवेश द्वार पर आगंतुकों की पहचान सत्यापित करने के लिए एहतियाती उपायों और बच्चों की चोरी संबंधी चिंताओं का हवाला दिया। अस्पताल प्रशासन की ओर से घटना या बुर्का हटाने की कथित मांग के पीछे की परिस्थितियों की तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई।

बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। एससीओ बैठक में भारत, चीन और रूस सहित दस अन्य सदस्य देश शामिल है। पीएम मोदी ने कल सोमवार को किर्गिस्तान की अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन बैठकों में विभिन्न पहलुओं और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस साल यह उनकी पहली मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेता दिसंबर 2025 में दिल्ली में 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, गतिशीलता और लोगों के बीच आपसी संबंधों समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों पर भारत–रूस अंतर–सरकारी आयोग के 27वें सत्र के नतीजों का स्वागत किया, जो 24 अगस्त 2026 को मॉस्को में आयोजित हुआ था। दोनों नेताओं ने खासकर 2026 में भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन समेत, बहुपक्षीय मंचों पर भारत–रूस सहयोग पर विचार–विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह 12–13 सितंबर 2026 को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। आपको बता दें, 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है।

कौशांबी पटाखा फैक्टरी विस्फोट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख, 11 लोगों की हुई थी मौत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मनौरी गांव स्थित पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण धमाके में 11 लोगों की जान चली गई, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं और आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन के मुताबिक फैक्टरी का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के कौशांबी में पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट में लोगों की मौत बेहद पीड़ादायक है और उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अधिकारियों के अनुसार कौशांबी जिले में सोमवार दोपहर हुए भीषण विस्फोट में आठ बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, फैक्टरी का लाइसेंस 2024 में ही रद्द कर दिया गया था। मुर्मू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में हुए हादसे में लोगों की जान जाने की खबर बेहद पीड़ादायक है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।'' कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के बीच बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), पुलिस, दमकल और वायुसेना के कर्मियों की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं।

असम सरकार ने बाढ़ पीड़ित परिवारों को अंतरिम राहत के रूप में 25 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने मंगलवार को कहा कि इस वर्ष राज्य के तीन जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण प्रभावित 16,746 परिवारों के खाते में अंतरिम राहत के रूप में कुल 25.12 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों के

प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को 15–15 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री सरमा ने जापानी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 'मुख्यमंत्री फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल हंट' के तहत भी धनराशि जारी की। प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण सहायता के रूप में तीन किस्तों में एक लाख रुपये दिए जाएंगे, साथ ही नौकरी मिलने के बाद सहायता के रूप में प्रति उम्मीदवार 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने 'मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना' के तहत सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वालों को भी वित्तीय सहायता वितरित की। सरमा ने बताया कि 48,188 उम्मीदवारों को कुल 118.6 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक उम्मीदवार को एक वर्ष तक प्रति माह 2,500 रुपये मिलेंगे।

वैश्विक बदलावों के बीच भारत अपनी विकास गति बनाए रखने में सक्षम – वित्त मंत्री सीतारमण

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी ग्रोथ की रफ्तार को कम किए बिना ग्लोबल इकॉनमी में हो रहे बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। उन्होंने देश की आयातित ऊर्जा और फर्टिलाइजर पर निर्भरता को भी स्वीकार किया। जी20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने भारत को चुनौतियों से निपटने में सक्षम अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। भारत कुछ घरेलू उत्पादन क्षमता होने के बावजूद कई उर्वरकों और उनके कच्चे माल का भी आयात करता है। वित्त मंत्री ने कहा, "हम कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े आयातकों में से एक हैं। हम विभिन्न प्रकार के उर्वरकों (यूरिया, अमोनिया, डीएपी) के बड़े आयातक हैं। देश के भीतर उत्पादन क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद हम आयातक हैं।" निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के आर्थिक प्रदर्शन ने यह दिखाया है कि वह विदेशों में होने वाले घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देने और अपनी ग्रोथ की गति को बचाए रखने में सक्षम है। उन्होंने कहा, "ये सभी एक जीवंत अर्थव्यवस्था के बहुत स्पष्ट संकेत हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो वैश्विक स्तर पर बदलावों को स्वीकार करती है और खुद को इस तरह से ढालती है कि हमारी ग्रोथ प्रभावित न हो।" निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भी समय–समय पर अर्थव्यवस्था का अपना आकलन जारी करता है, जिसमें संकेतक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, "हां, चुनौतियां हैं, और हम सरकार के तौर पर हर बार चुनौती आने पर भारत को फायदेमंद स्थिति में लाने के लिए काम करेंगे।" भारत ने वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे लगातार बाहरी दबावों के बीच हासिल किया गया है। उन्होंने कहा, "इन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी इस वित्त वर्ष 2026–2027 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

'सूखा-मुक्तभारत' के लक्ष्य के लिए वाटरशेड विकास को गति दें - शिवराज सिंह चौहान

'नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक की प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्यों से परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर स्पष्ट एवं मापनीय परिणाम सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने वाटरशेड विकास को 'विकसित भारत के लिए सूखा–मुक्त भारत' के लक्ष्य को साकार करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल जल संरचनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि खेतों तक पानी पहुंचाना, भूमि की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय एवं आजीविका को मजबूत करना है। के तहत अब तक 52.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 1,220 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत 12,404 करोड़ रुपए है, जिसमें 8,134 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सेदारी है। केंद्रीय हिस्सेदारी में से 6,955.75 करोड़ रुपए यानी 85: राशि जारी की जा चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वाटरशेड विकास केवल जल संरचनाएं बनाने का कार्यक्रम नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य खेत में पानी पहुंचाना, भूमि की उत्पादकता बढ़ाना और किसान की आय एवं आजीविका को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर बूंद पानी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और उसका लाभ किसान तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने किसान–केंद्रित परिणामों को वाटरशेड परियोजनाओं की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना बताया। उन्होंने कहा कि वाटरशेड हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप लगभग 1.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जहां पहले एक फसल लेना भी मुश्किल था, किसान अब दो और कई स्थानों पर तीन फसलें ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बागवानी, सब्जी उत्पादन और उच्च मूल्य वाली फसलों का भी विस्तार हुआ है। इससे किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार आया है। चौहान ने कहा कि किसानों के जीवन में आया यह बदलाव ही योजनाओं की वास्तविक सफलता है।

नागा विधायकों ने अमित शाह से कुकी–जो नेताओं पर कार्रवाई की मांग की

मणिपुर, (एजेंसी)। मणिपुर के 9 नागा विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वे राज्य में हाल की घटनाओं और छह नागा नागरिकों की कथित हत्या और उनके शवों को क्षत–विक्षत करने के मामले में कुकी–जो नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में नागा विधायकों ने केंद्र से उन कुकी–जो नेताओं की तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से छह नागा नागरिकों की हत्या और उनके शवों को क्षत–विक्षत करने की जिम्मेदारी ली थी। विधायकों ने डिप्टी सीएम नेमचा किपजेन और उनके पति केएनएफ–पी के थांगबोई किपजेन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की और कुकी उग्रवादी समूह और हाल की घटनाओं के बीच संबंध होने का आरोप लगाया। ये आरोप पत्र में लगाए गए थे और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। विधायकों ने कुकी उग्रवादी समूहों के साथ 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स' (एसओओ) समझौते को तुरंत रद्द करने की भी मांग की, जिसका कारण उन्होंने बार–बार उल्लंघन और नागरिकों पर हमले बताए। पत्र में 27 अगस्त को इंफाल–तामेंगलोंग रोड पर हुए हमले का भी जिक्र किया गया, जिसमें चार नागा लोग मारे गए थे, साथ ही एनएच–202 पर टीएम कासोम में हुई पिछली घटनाओं और लंगका गांव पर कथित हमले और आगजनी का भी जिक्र किया गया, जिसमें दो किसान मारे गए थे। विधायकों ने चेतावनी दी कि अगर मांगी गई कार्रवाई नहीं की गई, तो उनके लिए मणिपुर सरकार का समर्थन जारी रखना मुश्किल हो सकता है।

नंदीग्राम के विकास को लेकर ममता पर बरसे सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से हारने के बाद बदले की भावना से वहां के लोगों को विकास कार्यों से वंचित रखा। गौरतलब है कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से सुवेंदु अधिकारी ने लगभग 2,000 वोटों के अंतर से हराया था। बाद में ममता बनर्जी ने उसी वर्ष दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद बरकरार रखा और लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनीं। सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ष्पिछले पांच वर्षों (2021 से 2026) में नंदीग्राम के लोगों को विकास कार्यों से दूर रखा गया। ममता बनर्जी 2021 में यहां से हारने के कारण नाराज थीं और इसी वजह से उन्होंने नंदीग्राम की उपेक्षा की।ष उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में रेलवे स्टेशन बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसके लिए सिर्फ छह एकड़ जमीन की जरूरत थी, लेकिन पिछली सरकार ने जमीन तक आवंटित नहीं की। अधिकारी ने दावा किया, ष्मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने रेलवे स्टेशन के लिए 3.5 एकड़ जमीन आवंटित कर भारतीय रेलवे को सौंप दी है। बाकी जमीन भी जल्द दी जाएगी। नंदीग्राम रेलवे स्टेशन का निर्माण अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। उस स्टेशन से ट्रेन में बैठने वाला पहला व्यक्ति मैं ही बनूंगा।

राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित होंगे प्राथमिक विद्यालय ठेउंगा मे तैनात प्रधानाध्यापक पंकज द्विवेदी

ठेउंगा के सरकारी स्कूल की बदली तस्वीर,नवाचार और बेहतर शिक्षण व्यवस्था से बढ़ा अभिभावकों का भरोसा

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या।आज कुछ वर्ष पहले कभी जिस प्राथमिक विद्यालय ठेंउगा में महज 18 बच्चे पढ़ते थे,आज उसी विद्यालय में 171 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।इस विद्यालय की तस्वीर बदलने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक पंकज कुमार द्विवेदी का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार–2025 के लिए हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से शिक्षा विभाग में खुशी की लहर है।राज्य शिक्षक पुरस्कार से चयनित होने के लिए बीएसए लाल चंद्र सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।बताते चले कि वर्ष 2014 में तत्कालीन बीएसए ने पंकज कुमार द्विवेदी को विद्यालय को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी।15 फरवरी 2014 को कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने इसे महज नौकरी नहीं,बल्कि जिम्मेदारी और मिशन के रूप में लिया।उन्होंने उस क्षेत्र मे सभी के घर–घर जाकर अभिभावकों से संपर्क किया और बच्चों को इस विद्यालय मे भेजने के लिए प्रोत्साहित किया।साथ ही साथ समय के अनुसार अत्याधुनिक सुविधाओं से इस विद्यालय को सुसज्जित किया। वहां पर पढ़ने आने वाले बच्चों पर सिर्फ खानापूर्ति ना करता बल्कि अपने घर के बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया जिसका नतीजा यह रहा दिन पर दिन इस स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती गई और अभिभावकों का भरोसा भी इन पर बढ़ता गया।प्रधानाध्यापक पंकज द्विवेदी ने विद्यालय में तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया। वही उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग के साथ–साथ अपने खर्च से चार स्मार्ट कक्षाएं तैयार कराईं।पहली स्मार्ट कक्षा वर्ष 2021 में कक्षा चार के लिए बनाई गई थी,जिसका उद्घाटन तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने किया था।आज विद्यालय के बच्चे स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई करने के साथ ऑनलाइन शिक्षण का भी लाभ उठा रहे हैं।उनके प्रयासों से विद्यालय में न केवल बच्चों की संख्या बढ़ी बल्कि शैक्षिक माहौल, अनुशासन, शिक्षण पद्धति और अभिभावकों के विश्वास में भी उल्लेखनीय बदलाव आया।यही वजह है कि सरकारी विद्यालय के प्रति ग्रामीणों का नजरिया बदला और अभिभावक अपने बच्चों को यहां पढ़ाने के लिए प्रेरित हुए।काशी नाथपुर मूलनिवासी पंकज द्विवेदी ने एसएमबी इंटर कॉलेज से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया।इसके बाद साकेत महाविद्यालय से स्नातक एवं परास्नातक तथा बीपीएड की पढ़ाई की।वर्ष 2009 में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए।

पंकज द्विवेदी की इस उपलब्धि पर बीएसए लाल चंद्र समेत विभागीय अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों तथा शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी।अधिकारियों ने कहा कि उनका कार्य अन्य शिक्षकों के लिए भी प्रेरणादायी है।एक छोटे से

विद्यालय को बेहतर शिक्षण व्यवस्था और नवाचार के माध्यम से नई पहचान दिलाना निश्चित रूप से सराहनीय उपलब्धि है।

संपादकीय

संदेह और एतराज

बीते कुछ वर्षों में अचानक ऐसा क्या हो गया, जिससे भारतीय खाद्य पदार्थ दुनिया में संदेह और एतराज का निशाना बनने लगे हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने अंदर झांकना होगा। इस शिकायत में सच्चाई हो सकती है कि भारत से खराब संबंधों के कारण ने चीन ने जेनेटिकली मॉडिफाइड होने का आरोप लगाकर भारतीय चावल की कुछ किस्मों का आयात रोका है। मगर, यही बात जापान के भारतीय आमों का आयात रोकने या कई देशों के भारतीय मसालों का आयात रोकनेध घटाने को लेकर नहीं कही जा सकती। वैसे, गुजरे चार वर्षों में मिलावट और गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के कारण भारतीय दवाओं पर भारतीय दवाओं के निर्यात पर भी खराब असर पड़ा है। इस दौरान अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों ने भारतीय दवाओं की खेप को वापस भेजा या आयात रोक दिया, जिससे भारत की ष्फार्मेसी ऑफ द वर्ल्डष् वाली छवि को चुनौती मिली। हालांकि, जापान भारतीय आम का सबसे बड़ा खरीदार नहीं था, लेकिन आम उत्पादकों के मुताबिक उसके प्रतिबंध से दुनिया में बहुत खराब संदेश गया है, जिसका असर आने वाले वर्षों में पड़ सकता है। इसका कारण जापान का विकसित देश होना और उसके परीक्षण प्रतिमानों की ऊंची छवि है। बहरहाल, मुद्दा है कि बीते कुछ वर्षों में अचानक ऐसा क्या हो गया, जिससे भारतीय उत्पाद दुनिया में संदेह और एतराज का निशाना बनने लगे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने अंदर झांकना जरूरी है। विशेषज्ञ भारत के कृषि उत्पादों की प्रमाणन व्यवस्था और विकसित देशों के खाद्य सुरक्षा प्रतिमानों के बीच बढ़ती गई खाई की ओर इशारा करते रहे हैं। वहां प्रतिमान समय के साथ विकसित हुए। खासकर कोविड–19 महामारी के बाद अनेक बाजारों में इन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। लेकिन इस दौर में भारत में परीक्षण और प्रमाणन की व्यवस्थाओं को उन्नत नहीं किया गया। जबकि थाईलैंड, वियतनाम, ब्राजील, चिले आदि जैसे अनाज निर्यातकों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांगों के अनुरूप अपने यहां प्रमाणन व्यवस्था बेहतर करने में जरूरी निवेश किया। उन्होंने उत्पादों के जीएमओ मुक्त होने के अधिाक विश्वसनीय सर्टिफिकेशन के इंतजाम किए। नतीजतन, भारत की कीमत पर उन देशों के उत्पाद बाजार हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में औद्योगिक उत्पादों के निरीक्षण की व्यवस्था अधिक कमजोर एवं भ्रष्टाचार ग्रस्त हुई है। उसका नतीजा अब भुगतना पड़ रहा है।

शरीर फूल गया लेकिन उसमें ताकत नहीं बची

हरिशंकर व्यास

भारतीय जनता पार्टी कभी आंदोलन करने वाली पार्टी थी। जब उसके दो सांसद थे तब उसने देश भर में राममंदिर का आंदोलन खड़ा किया था। यह उसके संगठन की ताकत थी और उसके बड़े नेताओं की वैचारिक व सांगठनिक ईमानदारी थी कि पार्टी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाई। भाजपा के संगठन के लिहाज से कहें तो नब्बे का दशक उसका स्वर्णिम समय था। एक तरफ राममंदिर का आंदोलन चल रहा था और दूसरी ओर जब उसके काउंटर में मंडल का आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें भी भाजपा ने अपने समर्थक समूहों को आंदोलित करके मंडल के खिलाफ भी एक व्यापक नैरेटिव बनाया था। मंदिर आंदोलन और मंडल विरोधी आंदोलन ने भाजपा को इतना ताकतवर बनाया कि नब्बे के दशक में उसने तीन बार सरकार बनाई। पहले 13 दिन की, फिर 13 महीने की और फिर पांच साल की। भाजपा उस समय विचारधारा वाली पार्टी थी। चाल, चेहरे और चरित्र की बात करती थी। भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। लगातार छह साल तक सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा का वह चरित्र काफी हद तक बचा हुआ था। उसका जीवंत संगठन था और कई बार सरकार के साथ संगठन का भी टकराव हुआ। भाजपा और संघ के संगठन जैसे भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागण मंच आदि सरकार पर दबाव बनाए रखते थे। अब पिछले 12 सालों में क्या हुआ? भाजपा, उसके अनुषंगी संगठन और संघ के संगठनों की आंदोलन की क्षमता लगभग समाप्त है। वह किसी भी तरह के आंदोलन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर पा रही है। अब सब कुछ सरकार के भरोसे है। संगठन के लोग आराम से बैठे हैं कि सब सरकार देख लेगी। सरकार कैसे देख लेगी! सरकार के पास एजेंसियां हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए आदि एजेंसियां हैं और उससे भी ऊपर न्यायपालिका है। याद करें कैसे 2011 और 2012 में दिल्ली में आंदोलन हुए थे। उस समय तक भाजपा और संघ की आंदोलन को प्रभावित करने की क्षमता थी। तभी चाहे वह आंदोलन अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का हो या बाबा रामदेव का हो या निर्भया कांड के विरोध में हुआ आंदोलन हो, हर आंदोलन के दौरान कांग्रेस और उसकी सरकार परेशान हुई। यह आरोप लगाया कि भाजपा व संघ इन आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। यह बात काफी हद तक सही थी कि सीधे आंदोलनों में शामिल होकर उनका नेतृत्व करने की बजाय भाजपा और संघ ने उस समय के जन आक्रोश को परदे के पीछे से एक दिशा दी और उसका राजनीतिक लाभ लिया। आज भाजपा और संघ या कांग्रेस राज के समय इनके द्वारा तैयार किए गए गुरू और प्रवचनकर्ता, कोई भी आंदोलन खड़ा करने में अक्षम हैं। उलटे भाजपा और संघ के संगठनों की ताकत इतनी कम हो गई है कि सरकार के खिलाफ होने वाले किसी आंदोलन के समानांतर न तो कोई दूसरा आंदोलन कर पाए और न उसे डिफ्यूज कर पाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों समझ रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं तो बाकी चीज की कोई जरुरत नहीं है। उनको यह भी लग रहा है कि उन्होंने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दी तो अब क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी में कोई दम नहीं दिख रहा है। ऐसा सग रहा है कि पार्टी का शरीर फूल गया लेकिन उसमें ताकत नहीं बची है। सोचें, सरकार में आने के बाद से नरेंद्र मोदी को कितनी बार आंदोलकारियों ने झुकाया! यूपीए सरकार के समय के भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का कानून नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई थी। लेकिन इतना आंदोलन हुआ कि सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। ऐसे ही कृषि कानून मोदी सरकार ने बनाए थे और कहा था कि इससे किसानों की किस्मत बदल जाएगी। एक साल तक आंदोलन करके किसानों तीनों कानून वापस कराए। राष्ट्रीय टीवी पर माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिया। सरकार और भाजपा के नेता कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सरकार के पास नैतिक बल नहीं है और संगठन की शक्ति नहीं है। अगर संगठन और विचारधारा बची रहती तो पेपर लीक होने और परीक्षा में गड़बड़ी होने पर संघ का छात्र संगठन और भाजपा का युवा संगठन भी आंदोलित होता। वह कॉकरोच जनता पार्टी को आंदोलन का स्पेस नहीं लेने देता। लेकिन सारे छात्र व युवा नेता इस अति आत्मविश्वास में बैठे रहे कि सरकार सब संभाल लेगी। माना गया कि पुलिस लाठी चला कर छात्रों को भगा देगी और कुछ नहीं होगा। सोचें, एक समय भाजपा स्वंय बड़े आंदोलन खड़े करती थी या हर लोकप्रिय आंदोलनों के पीछे उसका किसी न किसी रूप में हाथ होता था। लेकिन अब उसकी सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो जा रहा है, किसान और छात्र व युवा उसे सरकार को झुकाने का माध्यम बना रहे हैं और भाजपा का मुख्य संगठन या उसके दर्जनों अनुषंगी संगठनों को जंग लग गई है।

मनुस्मृति में नारी को लेकर ऐसा लिखा , जिस पर होता है बवाल

अभिनय

गोरख पांडे के इन शब्दों को अगर आज के समाज की असलियत कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। सोचिए एक किताब जिसे कुछ लोग धर्म की बुनियाद मानते हैं और वहीं कुछ लोग उसे सरेआम जलाकर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के सबसे असरदार और शायद सबसे विवादित ग्रंथ की मनुस्मृति की। आप में से कितने लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा है? आप में से बहुत सारे लोगों ने गीता को पढ़ा होगा। रामचरितमानस को पढ़ा होगा, महाभारत को पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने प्राचीन पुस्तकों को जो अलग–अलग पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ा होगा। वेदों को पढ़ा होगा और इनसे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ऐसी ही एक प्राचीन पुस्तक है जिसे हम कहते हैं मनुस्मृति। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मनुस्मृति को अपना निशाना बनाया है। पुणे में छात्रों की गूंज नाम के अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों से बात की थी और इस दौरान राहुल गांधी ने मनुस्मृति में एक श्लोक का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे यह किताब महिलाओं की आजादी के खिलाफ है और इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। ऐसा राहुल गांधी ने कहा। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी बार–बार मनुस्मृति को ही अपना निशाना क्यों बनाते हैं? इस किताब का पूरा नाम मानव धर्म शास्त्र है। तो आज सबसे पहले आपको मनुस्मृति के बारे में बताते हैं। जब हम भारत में धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो अमूमन शुरुआत में दो प्रकार के ग्रंथ देखने को मिलते हैं। एक जिनको हम श्रुति ग्रंथ कहते हैं जिनको सुना गया समझा गया। एक उनको स्मृति ग्रंथ जिनको सुनने के बाद याद किया गया और फिर उसे लिखा गया। कई बार इनको उनके डिसाइपल्स द्वारा लिखा गया। तो श्रुति के बाद स्मृतियों का जो महत्व है। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म की अगर बात करें तो प्राचीन में बहुत सारे ग्रंथ जो थे वो इन्हीं विधियों से होकर आगे बढ़े हैं। वेदों की बात करें या अरण्यकों की बात करें। ब्राह्मस्य की बात करें या उन स्मृतियों की बात करें जिनमें से एक मनुस्मृति है। स्मृतियों की बात करें तो कुल लगभग 18 स्मृति है। अगर हम धर्मशास्त्र की बात करें तो 18 स्मृति है। जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति और बहुत सारी। इनमें से पहली स्मृति मनुस्मृति को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा थे उन्होंने मनु को ज्ञान दिया। ठीक है? मनु ने यही ज्ञान अपने शिष्य भृगु को दिया और भृगु ने अपने इस ज्ञान को आगे मानवता तक बढ़ाया। शुरुआत में ज्ञान की परंपरा को ऐसे बताया गया है। इस किताब में 12 अध्याय हैं और लगभग 2694 श्लोक इस किताब में हैं। हिंदुओं की ऐसी मान्यताएं है कि इस पुस्तक को सृष्टि के पहले इंसान ने लिखा था और उन्होंने ही इसके जरिए मानवता को तमाम तरह के कानून दिए। मतलब जो सृष्टि में पहला मनुष्य है उसने इसे लिखा। इसीलिए इसे मनुस्मृति कहा जाता है। यहां मनु का मतलब है पहला मनुष्य। हालांकि कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह पुस्तक आज से लगभग 2000 वर्ष पहले यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर के के आसपास लिखी गई है और 200 ईसा पूर्व से 200 ईसवी के बीच इसे लिखा गया है। इस ग्रंथ में मनु ने जीवन दर्शन, प्रशासन, समाज की रचना, नीतियां और कानून के बारे में विस्तार से बताया है। यानी समाज को कैसे चलाना है। राजा से लेकर प्रजा तक सबका धर्म क्या होना चाहिए? आचार विचार क्या होना चाहिए? व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये सारी बातें इस पुस्तक में बताई गई है। यह जीवन जीने की एक पूरी पद्धति है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय यह पुस्तक लिखी गई तब तक ना तो बाइबल लिखी गई थी और ना ही कुरान लिखी गई थी। शासन और प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था में इस पुस्तक का इस्तेमाल ना सिर्फ भारत में बल्कि कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी हुआ जहां पर हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने हिंदू कोड बनाने में इस ग्रंथ का काफी इस्तेमाल किया था।

लेकिन आजाद भारत के कानून में हमारे संविधान में इस पुस्तक की कोई जगह नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूजयंते रमंते तत्र देवता। हिंदी में इसका मतलब है जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह पुस्तक आज से लगभग 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसे आज की नैतिकता से जज नहीं किया जा सकता। बाइबल दास प्रथा को, भी कहा गया है कि शूद्रों और महिलाओं को भी धर्म के रास्ते पर चलने का पूरा हक है। 2026 के एक फैसले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक विधवा के गुजारे भत्ते के अधिकार को सही ठहराने के लिए मनुस्मृति का ही हवाला दिया था। ये दिखाता है कि ये महज इतिहास के पन्नों में दबी हुई कोई किताब नहीं है। और ये कोई एक आध बार नहीं हुआ है। 2019 से पहले ही सुप्रीम कोर्ट सात से भी ज्यादा बार अपने फैसलों में मनुस्मृति का जिक्र कर चुका था। अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो वहां तो इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा होता रहा है। 25 दिसंबर, 1927 का दिन था जब डॉ. अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया। अंबेडकर ने पहले से घोषणा कर दी थी कि वह इस हिंदू ग्रंथ को जलाएंगे। जो जगह उन्होंने इसके लिए चुनी वो महाड़ नाम का महाराष्ट्र का तटीय इलाका था, जो कोलाबा (अब रायगढ़) जिले में था। अंबेडकर मनुस्मृति को जातिवादी और पितृसत्तात्मक मानदंडों के खिलाफ मानते थे। बकौल उनके, मनुस्मृति ऐसा हिंदू ग्रंथ है, जो जाति उत्पीड़न को संस्थागत बनाता था। निचली जातियों, विशेषकर दलितों और महिलाओं के शोषण और भेदभाव को उचित ठहराता था। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर इसका विरोध किया था उन्हीं ने बाद में हिंदू कोड बिल की बहस में महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक दिलाने के लिए मनुस्मृति के ही कुछ प्रोग्रेसिव श्लोकों का इस्तेमाल किया। डॉ. बी आर आंबेडकर ने यह तर्क दिया था कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात ऋषि मनु जैसे स्मृतिकारों द्वारा कही गई थी।

देशभक्ति के बाद अब हिन्दू होने का भी सर्टिफिकेट

मोहन

राहुल ने देश की राजनीति से हिन्दू मुसलमान के सवाल को हटाकर शिक्षा, स्कूल, नौकरी, गरीबी, महंगाई जैसे असली सवालों को ला खड़ा किया है। इसकी कोई काट मोदी के पास नहीं है। इसलिए भागवत उनकी मदद के लिए आए हैं। और हिन्दू–मुसलमान को नए रंग में लाकर कोशिश कर रहे हैं कि देश में अजेंडा फिर इसी मुद्दे पर सेट हो जाए। राजनीतिक खबरें पढ़ें राहुल की बातों और मोहन भागवत की बातों में यही फर्क है। राहुल जो कहते हैं करने के लिए और मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक जो कहते हैं वह सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए। और सामने उनके अपने ही लोग होते हैं उन्हें ही मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। समस्या यह है कि उनकी पूरी ट्रेनिंग ही नकारात्मक विचारों के बीच हुई है। यह मानकर कि कु छ भी कहा जा सकता है और किया उसका ठीक उल्टा भी जा सकता है।भागवत जी अमेरिका में हिन्दुओं पर ही सवाल उठा रहे हैं। उन्हीं हिन्दुओं पर जिनके

लिए सौ साल पहले उनका संगठन बना था और आज भी वह नहीं कहता कि यह भारतीयों का संगठन है, वही कहता है कि हिन्दुओं का संगठन। वहां न्यूयार्क में वे कहते हैं कि जो हिन्दू यह समझता है कि मुस्लिम भारत में नहीं रह सकते वह हिन्दू नहीं है। वाह! हालांकि यह बयान बहुत विरोधाभासी है और संघ के लिए इस तरह की बातें करना कोई नई चीज नहीं है मगर फिर भी इसकी छुपी हुई परतें खोलना होगीं। क्योंकि भाजपा संघ इसके सहारे अपने को उदार बताने की कोशिश करेगा और गोदी मीडिया इसका ढोल पीटेगा। जो उसने शुरू कर दिया हैतो नंबर एक यह बयान राहुल के छात्र– युवा, महिला, दलित, ओबीसी के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दिया गया है। और अपने एवं भाजपा के प्रिय विषय हिन्दू–मुसलमान पर फिर से बहस को लाने के लिए। हिन्दू–मुसलमान ही इनकी प्राण वायु है। वह कम होते ही यह छटपटाने लगते हैं। राहुल ने देश की राजनीति से हिन्दू मुसलमान के सवाल को हटाकर शिक्षा, स्कूल, नौकरी, गरीबी, महंगाई जैसे असली सवालों को ला खड़ा किया है। इसकी कोई काट मोदी के पास नहीं है। इसलिए भागवत उनकी मदद के लिए आए हैं। और हिन्दू–मुसलमान को नए रंग में लाकर कोशिश कर रहे हैं कि देश में अजेंडा फिर इसी मुद्दे पर सेट हो जाए।लेकिन वे राहुल को नहीं जानते। यह समय उनका आ गया है। और वे बहुत साफ कहते हैं कि भाजपा–संघ क्या कह रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर शनिवार को प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि– उनके कहने या न कहने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। और राहुल जब इस तरह संघ भाजपा के मुद्दों को नजरअंदाज करेंगे तो वह फिर देश का मुख्य मुद्दा बन ही नहीं सकता। और बिना हिन्दू–मुसलमान के मुद्दे के मोदी राजनीति नहीं कर सकते और भागवत संघ नहीं चला सकते।दूसरी बात भागवत ने यह बयान न्यूयार्क में दिया है। 2018 के एक कार्यक्रम का हवाला देकर। उसके बाद लंबा समय हो गया। 8 साल। भारत में भी यह बात कह सकते थे। मगर अमेरिका में कहा क्यों? क्योंकि वहां उनकी विभाजनकारी नीतियों का बहुत विरोध हो रहा है। लोग प्लेकार्ड लेकर सड़कों पर उतरे हैं। न्यूयार्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि मेरे पास अधिकार नहीं हैं वरना मैं किसी विभाजनकारी विचारधारा को यहां फैलाने की इजाजत नहीं देता। प्रवासी नेटवर्क जुड़ें न्यूयार्क बहुलतावादी विचारों का शहर है। और संघ के विचार इसके ठीक उलट हैं। उनके अलावा मानवाधिकार संगठनों ने साफ कहा कि संघ की विचारधारा असहिष्णुता और भेदभाव को बढ़ावा देती है। और वहां खासतौर से क्रिश्चयन की बात ज्यादा हुई कहा कि उनके और मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहले चर्च जलाने, उन्हें तोड़ने की ही घटनाएं हुईं।तो भागवत के लिए वहां अपनी सफाई देना जरूरी था। भारत के बाद दुनिया के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मगर विचार बदले बिना चोला बदलने से कुछ नहीं होगा। आज के जमाने में जब जानकारियां सबके पास हों तो आपका कहो कुछ करो कुछ नहीं चल सकता। संघ और भाजपा अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने कई चेहरे ही समझते थे। मगर जब तक आपको कुछ काम करने का मौका न मिले तब तक तो चल जाता है। लेकिन जब सत्ता में आ गए और साढ़े बारह साल हो गए तो सबको मालूम पड़ गया कि यह बोलते कुछ हैं और करते कुछ। अभी न्यूयार्क में जो कहा है उसका संबंध मुस्लिम से उतना नहीं है। जितना हिन्दू से है। उस हिन्दू से जिसे हमेशा मुस्लिम के खिलाफ भड़काते रहे। पचासों उदाहरण हैं। जिन्हें बार–बार बताने से कोई फायदा नहीं। सबको कुछ न कुछ याद हैं। उनसे अब कह रहे हैं कि अगर तुम मुस्लिम को भारत से बाहर करने की सोच रहे हो तो तुम हिन्दू नहीं! बताइये हिन्दुओं का सबसे बड़े ठेकेदार बनने वाला संघ अब उन्हें कह रहा है कि तुम हिन्दू नहीं! अभी तक देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते थे अब हिन्दू होने के भी बांटने लगे! क्या होगा गिरराज सिंह का जो सबको पाकिस्तान भेजा करते हैं। और वे मोदी सरकार में मंत्री हैं इसलिए उनका नाम सबसे ज्यादा याद आ जाता है मगर ऐसे जाने कितने इनके मुख्यमंत्री, सांसद और दूसरे नेता हैं जो भारत से निकालने के साथ और भी क्या–क्या कहते रहते हैं। भागवतजी क्या इन्हें हिन्दू धर्म से निकालेंगे? अब तो हालत यह कर दी है कि इनके नेता मुख्यमंत्री शंकराचार्यों को भी कुछ भी कह देते हैं। तो क्या भागवत जी वहीं विदेश से मैसेज देंगे कि ऐसे सभी लोगों को मैं भारत आने के साथ धर्म बाहर कर दूंगा? भागवत एक असफल प्रयास कर रहे हैं। नरेटिव बदलने का। जिस काम के मोदी एक्सपर्ट थे वे नहीं कर पाए तो अब भागवत के कहने से उनकी, मोदी की, संघ की, भाजपा की छवि नहीं सुधरने वाली। देश के साथ अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी अब यह स्थापित हो गया है कि संघ भाजपा मोदी विभाजनकारी विचारों के हैं। बहुलतावाद के विरोधी। इसीलिए भागवत को विविधता में एकता कहना पड़ा। यही तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। और राहुल संविधान की प्रति लेकर यही तो बताते हैं। आज जब देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी के खिलाफ दक्षिण के राज्यों के खिलाफ, विभिन्न खान–पान के खिलाफ यहां तक की कपड़ों पर जिसे खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, भाषा, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है जिसे गर्व से कहते हैं डबल इंजन की सरकार वह कह रही है कि जिन ड्राइवरों को मराठी नहीं आती वे आटो टैक्सी नहीं चला सकते। ये हिन्दी वालों के ही खिलाफ है। वे ही हैं मुम्बई में आटो टैक्सी ड्राइवर। उन हिन्दी प्रदेशों से जहां सब जगह इनकी ही डबल इंजन सरकार है। हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्थान! इनका मुख्य नारा था। मगर जब देश से लेकर विदेश तक सब जगह इनकी नफरत और विभाजन की विचारधारा को मानवता विरोधी बताया जाने लगा तो भागवत को वहां न्यूयार्क में कहना पड़ा कि पूरी मानवता एक है। दरअसल नई पीढ़ी जिसे जेन जी और जेन अल्फा कहा जाता है ।

यह अंग्रेजों को फॉलो करने जैसा

अजीत द्विवेदी

देश में जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। पहले चरण में मकानों की गिनती के बाद अब नागरिकों की गिनती हो रही है। इसकी शुरुआत लद्दाख से हुई है। अभी स्वगणना का दौर चल रहा है और एक सितंबर से सरकारी कर्मचारी लद्दाख के हर घर में जाएंगे। देश के बाकी हिस्सों में नागरिकों की गिनती का काम अगले साल होगा। सरकार ने एक मार्च की आधी रात का समय संदर्भ तिथि के तौर पर तय किया है। उस दिन तक जिन लोगों का जन्म होगा उनकी गिनती होगी। लद्दाख में गिनती शुरू होने के साथ ही एक नए इतिहास की शुरुआत हुई। लद्दाख पहला क्षेत्र बना, जहां 1931 के बाद पहली बार जातियों की गिनती शुरू हुई है। आखिरी बार 1931 में अंग्रेजी राज में जाति जनगणना हुई थी। उसी के आंकड़े के आधार पर आज भी जातियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। आजाद भारत में पहली बार जाति जनगणना हो रही है और शुरुआत लद्दाख से हुई है। सो, कायदे से इसका बहुत प्रचार होना चाहिए था। हर छोटी बड़ी चीज को इवेंट में बदलने वाली भाजपा ने इसको अनदेखा कर दिया। कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके मंत्रालय में जनगणना का विभाग आता है, ने इसका श्रेय नहीं लिया। चुपचाप जातियों की गिनती शुरू हो गई। तभी इस प्रक्रिया को लेकर संदेह शुरू हुआ। जिस तरह से जाति जनगणना का प्रपत्र बना है उसमें सरकार जातियों की तय सूची नागरिकों को नहीं उपलब्ध करा रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़ कर बाकी नागरिकों पर छोड़ा गया है कि वे अपनी जाति बताएं। उनकी बताई जाति को ही जनगणना प्रपत्र में दर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाया है। असल में इसे लेकर भाजपा और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के बीच काफी समय से माथापच्ची चल रही थी। भाजपा और संघ दोनों को अंदाजा हो गया था कि जाति जनगणना व्यापक हिंदू एकता बनाने बनाए रखने में बाधा बन सकती है। संख्या सामने आने के बाद जातियां अपनी पहचान को लेकर ज्यादा मुखर होंगी और उससे राजनीतिक भागीदारी व सत्ता में हिस्सेदारी का संघर्ष और सघन होगा। समानता के नाम पर लाए गए यूजीसी के दिशानिर्देशों का नुकसान भाजपा और संघ दोनों को महसूस हो रहा था। यह भी दिख रहा था कि किस तरह से भाजपा और संघ का सबसे बड़ा समर्थक समूह यूजीसी के बहाने आरक्षण हटाओ का अभियान चला रहा है। एक तरफ आरक्षण बढ़ाने की मुहिम है तो दूसरी ओर आरक्षण हटाने की सीधी मांग है। आरक्षण हटाने की मांग करने वाला वर्ग भाजपा का पुराना और सबसे मजबूत समर्थक वर्ग है। इसके अलावा श्जेन जीच आंदोलन ने भी दिखाया है कि छात्रों और युवाओं को पुरानी पहचान के साथ बांधे रखना संभव नहीं होगा। उनके लिए विचारधारा और दूसरी किसी तरह की प्रतिबद्धता से पहले अपना हित आता है। तभी इस सवाल पर विचार हुआ कि क्या जाति जनगणना उनके हितों को पूरा करेगी? चूंकि अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती पहले से होती रही है। इसलिए उनकी जाति का नाम शामिल करने में कोई समस्या नहीं थी। परंतु पिछड़ा और सामान्य वर्ग की जातियों को दर्ज करने का काम नागरिकों के ऊपर ही छोड़ा गया है। सरकार को अंदाजा था कि जाति गणना भाजपा की राजनीतिक संभावना को कमजोर कर सकती है। परंतु मुश्किल यह थी कि सरकार जाति जनगणना की घोषणा कर चुकी थी और उसकी घोषणा से पहले बिहार, कर्नाटक व तेलंगाना में जाति गणना हो गई है। अगर भाजपा की केंद्र सरकार इससे पीछे हटती तो उसे कांग्रेस की ओर से होने वाले बड़े हमले का सामना करना पड़ता और तब यह आरोप भी लगता कि उसने बहुजनों के हित का ध्यान नहीं रखा। ध्यान रहे इस समय किसी भी प्रादेशिक नेता के मुकाबले राहुल गांधी बहुजन हितों के बड़े चौंपियन है। यह बात भाजपा को परेशान कर रही है। तभी उसे ऐसा रास्ता निकालना था, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सो, उसने जाति जनगणना में जातियों की सूची उपलब्ध नहीं कराने का फैसला किया। असल में सरकार के सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प वह था, जो बिहार सरकार ने जाति गणना में अपनाया था। उसमें बिहार की सभी जातियों की सूची नागरिकों के सामने रखी गई थी और उसमें से चुन कर उनको अपनी जाति बतानी होती थी। बिहार में कुल सवा तीन सौ से कुछ ज्यादा जातियां हैं, जिनकी सूची उपलब्ध कराई गई। अगर सचमुच सरकार गंभीर होती तो बिहार की तरह ही हर राज्य की जाति की सूची नागरिकों के सामने उपलब्ध कराई जाती और लोगों से उसमें से जाति चुनने को कहा जाता। अगर कोई कहता कि उसकी जाति का नाम सूची में नहीं है तो उसके लिए अन्य की एक अलग श्रेणी बनाई जा सकती थी। दूसरा विकल्प यह था कि जातियों की सूची नहीं दी जाए और नागरिकों को खुद ही जाति बताने को कहा जाए। इस तरीके से 2011 की जनगणना के समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने जातीय व सामाजिक गणना कराई थी। इसमें से सरकार ने पहला और ज्यादा वैज्ञानिक विकल्प नहीं चुना। उसने दूसरा विकल्प चुना। सरकार ने नागरिकों पर छोड़ दिया कि वह जाति बताए। इस तरह 2011 में जो जातीय व सामाजिक गणना हुई थी उसका क्या हश्र हुआ वह सबको पता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय नागरिकों ने 46 लाख के करीब जातियां दर्ज करा दीं। भारत में कुल तीन हजार के करीब जातियां हैं। लेकिन लोगों ने जाति, उपजाति और गोत्र आदि के नाम भी दर्ज करा दिए। इसलिए पूरी कवायद ही बेकार हो गई। अब एक बार फिर इसी तरीके से जातीय जनगणना हो रही है। इसका हश्र भी वैसा ही होगा। इससे धारणा के स्तर पर यह स्थापित हो जाएगा कि सरकार ने जातीय जनगणना कराई, लेकिन असल में उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बताया जा रहा है कि जातियों की सूची जारी करके जनगणना नहीं कराने का फैसला इस तर्क के आधार पर किया गया कि यह अंग्रेजों को फॉलो करने जैसा हो जाएगा। असल में अंग्रेजों ने जातियों की सूची बनाई थी और मोटे तौर पर वही सूची अभी तक चल रही है। अंग्रेज जाति की गणना उस सूची के आधार पर कराते थे। आजाद भारत की सरकार वैसे क्यों गिनती कराए, यह मैसेज बनाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया गया। लेकिन वह तरीका चालाकी से पूरे मामले को भटका देने वाला साबित होगा।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का किया निरीक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन एवं पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह द्वारा जिला कारागार का सोमवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कारागार के विभिन्न बैरकों,

अस्पताल एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कारागार अस्पताल में भर्ती बंदियों से अधिकारियों ने उनके स्वास्थ्य एवं उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने संबंधित चिकित्सकों एवं कारागार प्रशासन को बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पाकशाला का निरीक्षण करते हुए बंदियों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता की जांच की गई। अधिकारियों ने भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने तथा बंदियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने कारागार की सुरक्षा व्यवस्था, साफ–सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

मलिहाबाद के भुलसी गांव में तालाब से मिला दो दिन से लापता 25 वर्षीय युवक का शव

लखनऊ, (संवाददाता)। मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम भुलसी में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने गांव स्थित तालाब में एक युवक का शव पड़ा देखा। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मलिहाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को तालाब से बाहर निकलवाया।पुलिस के अनुसार मौके पर मौजूद परिजनों ने शव की पहचान विकास उम्र करीब 25 वर्ष, पुत्र कृष्ण कुमार, निवासी ग्राम भुलसी, थाना मलिहाबाद, लखनऊ के रूप में की। बताया गया कि विकास बीते 28 अगस्त 2026 से लापता था। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। रविवार को तालाब में शव मिलने की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया।पुलिस ने शव का मौके पर ही निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया शव पर किसी प्रकार की जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल बाहरी स्थिति के आधार पर युवक की मृत्यु के कारण के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

लाइसेंसी रिवॉल्वर, मोबाइल और चेन लूटने के मामले में 17 वर्षीय बाल अपचारी संरक्षण में

लखनऊ, (संवाददाता)। मोहनलालगंज थाना पुलिस ने लूट की घटना में वांछित चल रहे 17 वर्षीय बाल अपचारी को तकनीकी और स्थानीय सूचना के आधार पर संरक्षण में लिया है। पुलिस के अनुसार बाल अपचारी की तलाश काफी समय से की जा रही थी। मामले में पूर्व में चार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।पुलिस के मुताबिक 7 अप्रैल 2026 को वृंदावन योजना, थाना पीजीआई निवासी हेमन्त कुमार सोनी ने मोहनलालगंज थाने में तहरीर देकर बताया था कि बदमाशों ने उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर, मोबाइल फोन और गले की चेन छीन ली। शिकायत के आधार पर थाना मोहनलालगंज में मुकदमा अपराध संख्या 132ध्2026 दर्ज किया गया था।घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी। पुलिस के अनुसार 7 अप्रैल को रवि सिंह उर्फ विक्की सिंह और आर्यन सिंह, 8 अप्रैल को विशेष त्रिवेदी उर्फ राज पंडित तथा 13 अप्रैल को निखिल सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।इसके बाद घटना में शामिल अन्य वांछित आरोपियों की तलाश के लिए मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, मैनुअल जांच और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद ली जा रही थी। इसी क्रम में 30 अगस्त को पुलिस टीम ने एक 17 वर्षीय बाल अपचारी को संरक्षण में लिया।पुलिस के अनुसार बाल अपचारी से प्रकरण के संबंध में आवश्यक पूछताछ एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है।

डॉ. शम्भुनाथ की प्रथम पुण्यतिथि पर स्मृति समारोह

लखनऊ, (संवाददाता)। स्मृतिशेष डॉ. शम्भुनाथ की प्रथम पुण्यतिथि पर पारस बेला न्यास, कबीर शांति मिशन तथा डॉ. शम्भुनाथ के परिवार के संयुक्त तत्वावधान में गोमती नगर स्थित कबीर शांति मिशन में स्मृति समारोह आयोजित किया गया। समारोह में डॉ. शम्भुनाथ की कृति 'फिर आई याद कबीर की', डॉ. अनिल कुमार पाठक की कृति 'मम त्रैलोक्य' तथा डॉ. शम्भुनाथ के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित स्मृति–ग्रंथ 'शम्भु सुरभि' का विमोचन किया गया।मुख्य अतिथि प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित ने डॉ. शम्भुनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव जैसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। इससे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों में सचिव तथा कई जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में सेवाएं दीं। प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता और शुचिता के कारण उनकी कार्यशैली की हमेशा चर्चा होती रही।उन्होंने कहा कि डॉ. शम्भुनाथ के व्यक्तित्व का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष साहित्यकार का था। उन्होंने संवेदना के धरातल पर उतरकर अनेक काव्य कृतियों की रचना की। उनकी हिंदी कविताएं भी उल्लेखनीय हैं, जिनका प्रकाशन 'अतीत के गर्भ में' हुआ। कवि होने के साथ–साथ उनका समीक्षक रूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण था।

गोमती नदी में छलांग लगाने और कचरा फेंकने की घटनाओं पर लगेगी रोक, शाही पुल पर जाली लगाने का काम शुरू

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में ऐतिहासिक शाही पुल से गोमती नदी में छलांग लगाने और कूड़ा–कचरा फेंकने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शाही पुल के दोनों किनारों पर जाली लगाने का काम कराया जा रहा है। जाली लगने के बाद पुल से नदी में छलांग लगाना और कचरा फेंकना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा। शाही पुल जौनपुर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में शामिल है। इस पुल से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। पुल की ऊंचाई और नीचे बहती गोमती नदी के कारण यहां सुरक्षा को लेकर समय–समय पर चिंता जताई जाती रही है। पिछले कुछ वर्षों में पुल से नदी में छलांग लगाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे मामलों में पुलिस और स्थानीय लोगों ने कई बार मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया। इसके अलावा पुल से गुजरने वाले कुछ लोग नदी में कूड़ा–कचरा फेंक देते हैं। इससे गोमती नदी के जल की स्वच्छता प्रभावित होने के साथ ही आसपास का वातावरण भी खराब होता है। जाली लगने के बाद इस पर भी प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है। प्रशासन की ओर से जाली लगाने का काम तेजी से कराया जा रहा है। जाली की ऊंचाई और संरचना को इस तरह रखा जा रहा है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और पुल से नदी में वस्तुएं फेंकना भी कठिन हो। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे सुरक्षा और स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। लोगों का कहना है कि जाली लगने से शाही पुल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और गोमती नदी में कूड़ा–कचरा जाने की समस्या भी कम होगी। इस संबंध में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मनोरमा और ने बताया कि जाली लगाने की मांग काफी दिनों से चल रही थी आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए शाही पुल पर बेहतर और सुंदर दिखने वाली जाली लगाई जा रही है जिससे कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके साथ ही शाही पुल की सुंदरता भी बनी रहे। शाही पुल के दोनों किनारो पर जल्द ही रेलिंग का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। आगे इस पर बेहतर लाइट लगाने का भी काम किया जाएगा।

जौनपुर में तीन दिन से रुक–रुककर बारिश, शहर में जलभराव गोमती का जलस्तर बढ़कर 13 फीट पहुंचा,

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिले में पिछले तीन दिनों से रुक–रुककर हो रही बारिश से जहां लोगों को उमस से राहत मिली है, वहीं शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। आपदा विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में जिले में 38.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। दोपहर करीब एक बजे तक रुक–रुककर हुई बारिश के कारण प्रमुख सड़कों, गलियों और निचले इलाकों में पानी भर गया। मियांपुर पुलिस चौकी, कलेक्ट्रेट गेट और रुहट्टा क्षेत्र में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कालीकुत्ती, रुहट्टा, ईशापुर, एलआईसी कार्यालय के पीछे की गली और चांदमारी के पीछे की गली में भी जलभराव से यातायात प्रभावित रहा। रुहट्टा और तारापुर कॉलोनी में नालियों का मलबा सड़कों पर फैलने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। हालांकि, बारिश से धान की फसल को फायदा हुआ है। खेतों में हरियाली लौटने से किसानों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। आपदा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में इस वर्ष अब तक सामान्य रूप से 972.6 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, जबकि अब तक सिर्फ 161.99 मिमी वर्षा दर्ज हुई है। इस तरह सामान्य वर्षा की तुलना में करीब 83.3 फीसदी कम बारिश हुई है। लगातार बारिश के चलते गोमती नदी का जलस्तर भी धीरे–धीरे बढ़ रहा है। वर्तमान में नदी का जलस्तर करीब 13 फीट पहुंच गया है, जबकि खतरे का निशान 24 फीट है। जलस्तर बढ़ने से गोमतेश्वर महादेव मंदिर और गोपी घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। वहीं हनुमान घाट के चबूतरे तक भी पानी पहुंच गया है। यदि नदी का जलस्तर 15 फीट तक पहुंचता है तो बलुआघाट, चकप्यार अली, रामघाट और मियांपुर घाट के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है।

जन्माष्टमी को लेकर सजे जौनपुर के बाजार, लड्डू गोपाल के श्रृंगार सामानों की बढ़ी मांग

जौनपुर, 1 सितंबर । यूपी के जौनपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर जौनपुर शहर के बाजार सजने लगे हैं। चार सितंबर, शुक्रवार को मनाए जाने वाले जन्माष्टमी पर्व के मद्देनजर शहर के प्रमुख बाजारों में लड्डू गोपाल की प्रतिमाओं, आकर्षक पोशाक, मुकुट, बांसुरी, मोरपंख, झूले और साज–श्रृंगार की सामग्री की दुकानें सज गई हैं। पर्व नजदीक आने के साथ ही बाजारों में चहल–पहल भी बढ़ने लगी है। दुकानों पर लड्डू गोपाल की पोशाक 20 से 900 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध है। श्रृंगार सामग्री 20 से 400–500 रुपये, झूले 100 से 1000 रुपये, सिंहासन 150 से 700 रुपये, माला 10 से 200 रुपये और पगड़ी पांच से 400 रुपये तक में मिल रही है। राधा–कृष्ण की पोशाक भी 20 से 900 रुपये तक उपलब्ध है। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। इस बार बाजार में लड्डू गोपाल के लिए कई नई डिजाइन की सामग्री आई है। वृंदावन की पगड़ी, मथुरा के झूले, मोरपंखी मुकुट, मोती की माला और डायमंड जड़ित बांसुरी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। रेशम की गद्दी और तकिया के साथ विभिन्न रंगों व डिजाइन की पोशाक भी उपलब्ध है। डायमंड जड़ित झूले और मुकुट के साथ मोरपंखी आभूषण लोगों की पसंद बने हुए हैं। शहर के फलवाली गली स्थित बाबाजी की

दुकान के संचालक पवन साहू ने बताया कि अभी जन्माष्टमी के सामान की खरीदारी के लिए कम ग्राहक पहुंच रहे हैं। इसका एक कारण हाल ही में समाप्त हुआ रक्षाबंधन का बाजार भी है। उन्हें उम्मीद है कि अगले एक–दो दिनों में खरीदारी में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जन्माष्टमी की सामग्री के दाम में मामूली वृद्धि हुई है। भगवान के वस्त्रों की कीमत पांच से दस रुपये तक बढ़ी है, जबकि मुकुट, बांसुरी, आभूषण और अन्य सामग्री के दाम भी कुछ बढ़े हैं। वहीं, पुलिस लाइन स्थित राधा–कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर भव्य सजावट की तैयारियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। दुकान पर खरीदारी कर रही महिला कविता गुप्ता ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व भी काफी लोगों ने लड्डू गोपालकी की मूर्तियां खरीदी अभी बाजारों में हम लोग लड्डू गोपाल की मूर्तियां खरीद रहे हैं उनके कपड़े भी रंग–बिरंगे बाजारों में बिक रहे हैं जो बहुत ही आकर्षक हैं। भगवान के कपड़ों में कोई खास महंगाई नहीं है पिछली बार की अपेक्षा इस बार मार्केट में नई डिजाइनों भगवानके कपड़े बांसुरी राधा कृष्ण पोशाक अत्यंत आकर्षक है।

चरक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बी.एड. नवप्रवेशित विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित

लखनऊ, 1 सितंबर 2026। चरक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मोरा, लखनऊ में बी.एड. पाठ्यक्रम में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत एवं मार्गदर्शन के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बी.एड. पाठ्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण प्रक्रिया तथा शिक्षक के रूप में उनकी भावी भूमिका से परिचित कराना रहा। कार्यक्रम संस्थान की निदेशक श्रीमती रितु सिंह के आशीर्वाद एवं सहयोग तथा प्राचार्य डॉ. अनुराधा त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. अनुराधा त्रिपाठी ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने वाला मार्गदर्शक होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, नियमित अध्ययन, सकारात्मक सोच एवं निरंतर सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने का आह्वान किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में बी.एड. के सभी सेमेस्टरों के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों को सैद्धांतिक विषयों के साथ–साथ प्रायोगिक कार्य, विद्यालयी अनुभव, शिक्षण–अभ्यास, आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एवं अन्य प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी ज्ञान, डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, नवाचार, कौशल विकास तथा विद्यार्थी–केंद्रित शिक्षण पद्धतियों के बढ़ते महत्व पर भी विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम में बी.एड. विभागाध्यक्ष तथा विभाग के सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए उनके सफल शैक्षणिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों को सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और समर्पण के साथ बी.एड. प्रशिक्षण पूर्ण कर एक कुशल, संवेदनशील एवं जिम्मेदार शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करते हुए किया गया।

जौनपुर में अधिवक्ताओं ने आयु सीमा प्रस्ताव का किया विरोध कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन, 439 अधिवक्ताओं ने जताई थी असहमति

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मंगलवार को अधिवक्ता संघ के प्रस्तावित आयु सीमा संशोधन के विरोध में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ के पूर्व महामंत्री लाल बहादुर के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर का भ्रमण कर अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। अधिवक्ता शैलेन्द्र यादव ने बताया कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष घनश्याम सिंहऔर महामंत्री बृजेश मिश्रा की ओर से अधिवक्ताओं की आयु को लेकर एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव पर 439 अधिवक्ताओं ने असहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए और अध्यक्ष एवं महामंत्री को प्रार्थना पत्र सौंपा था। प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधिवक्ताओं ने मांग की थी कि इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर सभी पक्षों की बात सुनी जाए और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। उनका कहना है कि प्रार्थना पत्र दिए हुए 10 से 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अध्यक्ष और महामंत्री की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि संघ के मौजूदा बायलॉज में आयु अस्वीकृति (एज रिजेक्शन) की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि बायलॉज में प्रावधान नहीं होने के बावजूद आयु सीमा संबंधी व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो वे आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे।

राहुल गांधी पर मुकदमे के विरोध में कांग्रेस ने निकाला मार्च

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार शाम राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में शहर में विरोध मार्च निकाला। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह और शहर अध्यक्ष आरिफ खान के नेतृत्व में शाम सात बजे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुकदमा वापस लेने की मांग की। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच के कथित शुद्धीकरण की घटना के बाद राहुल गांधी ने प्रेसवार्ता कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उनके अनुसार, कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गे के मंच के कथित शुद्धीकरण की घटना सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय, संविधान और समानता के अधिकार के लिए आवाज उठाती रहेगी। भाजपा पर उन्होंने दलित विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ एससी–एसटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कथित मंच शुद्धीकरण की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की। मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने संविधान और सामाजिक समानता के समर्थन में नारे लगाए तथा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की।

समाज में सकारात्मक स्थायी परिवर्तन लाना लायन्स क्लब का मुख्य उद्देश्य – उदय चन्दानी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। लायन्स क्लब जौनपुर गोमती का 37वां अधिष्ठापन समारोह भव्यता एवं गरिमापूर्ण वातावरण में सम्पन्न लायंस क्लब जौनपुर गोमती का 37वां अधिष्ठापन समारोह रविवार की रात्रि शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में भव्य एवं गरिमापूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सेवा, समर्पण, अनुशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ क्लब की गौरवशाली परम्पराओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलन एवं विष्णुप्रिया द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना से हुआ। इसके पश्चात ध्वज वंदना एवं राष्ट्रगान के साथ समारोह को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया गया। क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने समारोह में पधारे अतिथियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनन्दन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलाध्यक्ष उदय चंदानी ने कहा कि क्लब का उद्देश्य केवल कार्यक्रमों का आयोजन करना नहीं, बल्कि सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक एवं स्थायी परिवर्तन लाना है। उद्घाटनकर्ता ळ।ज एरिया लीडर डॉ. क्षितिज शर्मा ने कहा कि नेपाल में जिस तरह से कुदरत का कहर बरपा था जिसका दंश पूरा देश आज उठा रहा है, सैकड़ों लोगों को अपनी जान ऐसे में लायंस क्लब इंटरनेशनल की एलसीआई ने तत्काल 24 घंटे में 2 लाख डॉलर की मदद भेजकर यह बात साबित कर दिया कि हमारी संस्था मानवता की सेवा के लिए ही कार्य कर रही है। अधिष्ठापन अधिकारी उपमंडलाध्यक्ष प्रथम उमेश चंद्र कक्कड़ तथा दीक्षा अधिकारी उपमंडलाध्यक्ष द्वितीय श्याम बाबू वर्मा सहित मंडल के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर आजम जैदी, आरिफ अनस, डा. सबाह, डा. एमएम खान ने क्लब की सदस्यता ग्रहण किया। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष लायन डॉ. राजेश मौर्या ने सत्र 2025–26 का अध्यक्षीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया वहीं सचिव लायन खुशबू गुप्ता ने सचिवीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अधिष्ठापन समारोह के दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं नवीन सदस्यों को लायंस क्लब की सेवा भावना, निष्ठा, अनुशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप शपथ दिलाई गई। समारोह में डि. डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रतिमा गुप्ता, कैबिनेट कोषाध्यक्ष सतीश टंडन, कैबिनेट च्स ब्रजेन्द्र बाजपेयी, रीजन चेयरपर्सन मनीष कुमार अग्रहरि, जोन चेयरपर्सन संजीव साहू सहित अनेक वरिष्ठ लायन सदस्य एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लायन सैय्यद हसनैन कमर 'दीपू' ने अपने संबोधन में कहा कि लायंस क्लब जौनपुर गोमती आगामी कार्यकाल में सेवा गतिविधियों को और व्यापक एवं प्रभावी स्वरूप प्रदान करेगा। उन्होंने सभी सदस्यों से क्लब की एकता, अनुशासन एवं सेवा भावना को और मजबूत करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुँचाने का आह्वान किया। नवनिर्वाचित सचिव लायन नवीन मिश्रा ने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग एवं सहभागिता से स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंदों की सहायता तथा जनकल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सेवा कार्य किए जायेंगे। समारोह में क्लब की प्रथम महिला डॉ तसनीम फात्मा, नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष ऋषिदेव, पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में क्लब के सदस्य सहित उनके परिवारजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का सफल संचालन लायन नवीन मिश्रा ने किया। समारोह के अंत में सभी अतिथियों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति मनीष गुप्ता व संयोजक गौरव श्रीवास्तव व शिव कुमार साहू ने व्यक्त करते हुए सेवा कार्यों को नई ऊर्जा, नई दिशा एवं दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन दिनेश टण्डन, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सिंह, सोमेश्वर केसरवानी, मेडिकल कालेज के सीएमएस डा. एए जाफरी, डा. मैहर अब्बास, फैसल हसन तबरेज पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस,शम्सी आजाद भाजपा नेता,अबूजर, ब्रह्मेश शुक्ला सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

सिविल लाइंस स्थित लक्ष्मी स्वीट हाउस में लगी भीषण आग

अयोध्या।नगर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित लक्ष्मी स्वीट हाउस में मंगलवार दोपहर बाद अचानक आग लगने से अफरा–तफरी मच गई।देखते ही देखते आग ने दुकान के अंदर रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई।घटना की सूचना मिलते ही सीएफओ एमपी सिंह तथा प्रभारी एफएसओ प्रदीप कुमार पांडेय ने चार दमकल व मनोज सिंह, हृदयनाथ विश्वकर्मा, कमलेश मिश्रा, अवधेश पांडे,सुनील तिवारी, सूर्य यादव, विवेक, प्रवीण, बृजपाल, सलाउद्दीन व अन्य फायर कर्मियों के साथ फायर कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने मे जुट गये।फायर कर्मियों की सक्रियता के चलते आग को समय रहते पूरी तरह काबू में कर लिया गया,जिससे आसपास के प्रतिष्ठानों तक आग फैलने से बच गई।लेकिन आग की चपेट में आने से स्वीट हाउस में रखा काफी सामान जलकर नष्ट हो गया।फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।इस संबंध। मे सीएफओ एमपी सिंह व सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी ने संयुक्त रुप से बताया कि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। आग बुझाने के दौरान किसी प्रकार के बढ़ाना उत्पन्न हो इसके लिए रूट डायवर्जेंट भी किया गया था।

'राज्यपाल व उपमुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश में शाहजहांपुर रेडक्रॉस करेगी मानव सेवा का विस्तार'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहाँपुर' लखनऊ स्थित राजभवन में आयोजित इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश शाखा की वार्षिक बैठक से जनपद शाहजहांपुर के लिए मानव सेवा के क्षेत्र में नई दिशा मिली है। महामहिम राज्यपाल एवं इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष आनंदीबेन पटेल तथा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश के सभापति ब्रजेश पाठक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अब शाहजहांपुर में रेडक्रॉस की गतिविधियों को और व्यापक एवं प्रभावी रूप दिया जाएगा।

राजभवन में हुई बैठक में जनपद शाहजहांपुर की ओर से डॉ रवि मोहन एवं डॉ विजय जौहरी, अनुज जौहरी ने सहभागिता की। बैठक में महामहिम राज्यपाल ने रेडक्रॉस की सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि 'बेटी पढ़ाओ' के साथ बेटियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यालयों में छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एच पी वी वैक्सीन के प्रति जागरूक करने तथा टीकाकरण में रेडक्रॉस की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर दिया। महामहिम ने विद्यालयों में फर्स्ट एड एवं सीपीआर प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आकस्मिक दुर्घटना या आपात स्थिति में चिकित्सकीय सहायता पहुंचने से पहले यदि शिक्षक एवं विद्यार्थी प्राथमिक उपचार और सीपीआर देना जानते हों तो कई बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने योग को विद्यार्थियों की जीवनशैली से जोड़ने पर भी विशेष बल दिया।

राज्यपाल ने गरीब एवं वंचित परिवारों के उन बच्चों की शिक्षा पर भी चिंता व्यक्त की, जो विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते और घरेलू कार्यों में लगा दिए जाते हैं। उन्होंने रेडक्रॉस को ऐसे बच्चों को चिह्नित कर उन्हें पुनः विद्यालय से जोड़ने और नियमित शिक्षा सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में रक्तदान को भी मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया। रक्तदाताओं की सूची तैयार रखने की आवश्यकता बताई गई, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। एक रक्तदान से एक से अधिक जरूरतमंद मरीजों को जीवनदान मिल सकता है, इसलिए रक्तदान को जनअभियान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। विशेष अभियान के तहत टी बी रोगियों को गोद लेकर उनको सहयोग देने पर विशेष बल दिया बैठक में उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अमित घोष ने होम्योपैथिक चिकित्सक एवं रेडक्रॉस से जुड़े डॉ रवि मोहन की चिकित्सीय सेवाभावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा के साथ रेडक्रॉस के माध्यम से सक्रिय रूप से मानव सेवा करना डॉ रवि मोहन की मानवीय संवेदना और सेवा–समर्पण का प्रतीक है। वहीं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रेडक्रॉस के सदस्य को जिला स्वास्थ्य समिति में नामित किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिससे जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में रेडक्रॉस की सहभागिता और प्रभावी हो सकेगी। राजभवन की बैठक से लौटने के बाद इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी शाहजहांपुर के सचिव डॉ विजय जौहरी ने कहा कि महामहिम राज्यपाल एवं उपमुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनपद में रेडक्रॉस की सेवाओं को नई गति दी जाएगी।

डॉ जौहरी ने कहा कि वे रेडक्रॉस के सचिव के रूप में जनपद के प्रत्येक उस समाजसेवी, संस्था और नागरिक का सहयोग चाहते हैं, जो मानव सेवा के प्रति समर्पित भाव रखता है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस किसी एक व्यक्ति की संस्था नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए समाज के सहयोग से चलने वाला मानवीय अभियान है। उन्होंने जनपदवासियों से आह्वान किया कि वे रेडक्रॉस से जुड़कर रक्तदान, फर्स्ट एड, स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा और जरूरतमंदों की सहायता के कार्यों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि "हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में शाहजहांपुर मानव सेवा के क्षेत्र में प्रदेश में अग्रणी जनपद के रूप में अपनी पहचान बनाए और रेडक्रॉस की सेवाओं के लिए सम्मानजनक स्थान प्राप्त करे। इसके लिए समाजसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवकों और जनसामान्य के सहयोग से निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

'शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए: जिलाधिकारी'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' जिलाधिकारी अनुनय झा ने कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। मंगलवार को जन सुनवाई में कुल 96 शिकायतें प्राप्त हुई जिसके त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा फरियादियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जनसुनवाई में प्राप्त कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान किया। जनसुनवाई में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मयंक कुंडू व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

महिला एसआई प्रिया ने मिशन शक्तिअभियान के तहत कैंट रेलवे स्टेशन व अन्य स्थानों पर जाकर महिलाओ को किया जागरुक

अयोध्या। मंगलवार को महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के निर्देश पर महिला उप निरीक्षक प्रिया ने कैंट रेलवे स्टेशन व अन्य स्थानों पर जाकर महिलाओ व रेल यात्रियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बताया। इसके साथ ही साथ उन्होंने महिला यात्रियों व महिलाओ को सुरक्षा के आवश्यक टिप्स बताये।कहा कि यात्रा के दौरान आप सभी संदिग्ध व्यक्तियों से सावधान रहें और संदिग्ध व्यक्तियों से खास कर दूरी बनाएं। कहा कि किसी भी वस्तु व्यक्ति को संदिग्ध रूप से दिखाई देने पर जीआरपी,आरपीएफ तथा स्थानीय पुलिस कर्मियों को बिना देरी किए सूचना दे जिससे किसी बड़ी घटना को होने से समय रहते बचाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने अन्य स्थानों पर खासकर गुरु गोविंद सिंह चौराहा,सिविल लाइन चौराहे पर महिलाओ को वीमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध। 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकती हैं।इस मौके पर उनके अलावा महिला होमगार्ड गीता, चंद्रावती अनीता, मनवती,राजकुमारी के अलावा अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रही।

हिमालय में 2300 ग्लेशियर झीलों पर साझा निगरानी तंत्र नहीं, तबाही ने खोली तैयारियों की पोल

गोरखपुर, (संवाददाता)। हिमालय की ऊंचाइयों पर जमा पानी कब मौत का सैलाब बनकर मैदानों में उतर आए, इसका अंदाजा लगाने के लिए देशों की सीमाएं काफी नहीं हैं। नेपाल में हालिया विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने हिमालयी क्षेत्र की आपदा तैयारियों की बड़ी कमजोरी सामने ला दी है। पाकिस्तान से भूटान तक करीब 2300 ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। इनमें से कई के टूटने पर अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। नेपाल में ही करीब 20 ग्लेशियर झीलें संवेदनशील हैं। इसके बावजूद पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए साझा और प्रभावी अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। नेपाल सरकार के आपदा सलाहकार और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्थित सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज के विशेषज्ञ डॉ. बसंत राज अधिकारी ने संवाद न्यूज एजेंसी से फोन पर बातचीत में कहा कि हिमालयी क्षेत्र की निगरानी किसी एक देश के बूते की बात नहीं है। भारत, नेपाल और चीन को मिलकर ग्लेशियर, ग्लेशियर झील, मौसम और नदियों की रियल टाइम निगरानी के लिए साझा तंत्र विकसित करना होगा। इस दिशा में नेपाल जल्द पहल करेगा। डॉ. अधिकारी के मुताबिक, 26 अगस्त की सुबह 8रू37 बजे फ्लैश फ्लड शुरू हुआ। करीब नौ बजे चीन की ओर से भारी बाढ़ की सूचना एसएमएस के जरिये मिली। इसके बाद सेना और पुलिस ने माइकिंग कर लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की लेकिन तब तक बाढ़ की रफ्तार इंसानी तैयारियों से कई गुना आगे निकल चुकी थी। पहाड़ से मलबा करीब 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आया। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका। उन्होंने इसे अब तक की सबसे विनाशकारी फ्लैश फ्लड बताते हुए कहा कि इसकी भयावहता अकल्पनीय थी। आपदा के वास्तविक कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पूरा ध्यान बचाव कार्य और लापता लोगों की तलाश पर है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. रमेश राज पंत ने बताया कि त्रिशूली नदी में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हैं लेकिन इनकी संख्या कम होने के कारण बाढ़ की सूचना समय पर नहीं मिल सकी।

जनसुनवाई में पार्षदों ने उठाई क्षेत्रीय समस्याएं, महापौर ने अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। सूर्यकुंड का मेला आगामी 17 सितंबर को आयोजित होगा।मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम सफाई, प्रकाश, शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था करेगा। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने मंगलवार को अयोध्या धाम कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई संभव में अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले से पहले संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को पूरा कर लें और आयोजन के दौरान भी कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।जनसुनवाई के दौरान महापौर के सामने 16 प्रकरण आए, जिनमें से नौ का मौके पर ही निस्तारण कराया गया।महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान नगर निगम की प्राथमिकता है। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और जरूरत पड़ने पर अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कराएं।गद्दोपुर में नगर निगम की भूमि पर पौधारोपण से संबंधित पैमाइश समय से न होने पर महापौर ने अधिकारियों को मौके पर जाकर पैमाइश कराने तथा जल्द से जल्द पौधारोपण कराने के निर्देश दिए। जनौरा के टड़वा में नाली निर्माण में विलंब की शिकायत स्थानीय नागरिकों ने की। इस पर महापौर ने संबंधित अधिकारियों को नाली का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।जनसुनवाई में अतिक्रमण, टैक्स, सफाई, जलभराव समेत अन्य समस्याएं भी सामने आईं। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया जाए, ताकि बारिश के दौरान नागरिकों को परेशानी न हो।नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनशिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पाण्डेय ने बताया कि इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव एवं सुमित कुमार, महाप्रबंधक जलकल सौरभ श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएम शुक्ल, जोनल अधिकारी ज्वाला प्रसाद, सुभाष त्रिपाठी, विनय सिंह, सहायक अभियंता सिविल राजपति यादव, भारत वर्मा तथा पार्षद मनीष चौधरी, अनुज दास, दीप कुमार, अंकित तिवारी, रिशु पांडेय आदि मौजूद रहे।

जिला अस्पताल में 14 और बीआरडी में 20 बेड सुरक्षित

गोरखपुर, (संवाददाता)। स्वाइन फ्लू की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले में फिलहाल स्वाइन फ्लू का कोई सक्रिय मरीज नहीं है। हालांकि जिले के तीन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी लेकिन उनकी जांच और उपचार लखनऊ में हुआ। एहतियात के तौर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स में स्वाइन फ्लू की जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जिला अस्पताल में 14 और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 20 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। सीएमओ डॉ. राजेश झा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पदाधिकारियों और निजी चिकित्सकों के साथ बैठक कर बीमारी की रोकथाम, जांच और उपचार को लेकर शासन की गाइडलाइन से अवगत कराया। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि संदिग्ध मरीजों की पहचान होने पर उनकी स्थिति के अनुसार उपचार किया जाए। गाइडलाइन के मुताबिक, प्रत्येक मरीज की जांच जरूरी नहीं है। गंभीर लक्षण वाले मरीजों की ही जांच कराई जानी है।

अनार लदी डीसीएम लेकर चालक चंपत

गोरखपुर, (संवाददाता)। गुजरात से करीब तीन लाख रुपये के अनार लेकर सिकरीगंज के लिए निकला डीसीएम चालक फल की खेप समेत रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। तेनुआ टोल प्लाजा पार करने के बाद चालक से व्यापारी का संपर्क टूट गया। डीसीएम और अनार की जानकारी नहीं मिलने पर व्यापारी ने पिपरौली चौकी में ट्रांसपोर्टर और चालक के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के इमलिडीहा निवासी मोहम्मद हसीब फल व्यापारी हैं। उन्होंने गुजरात के एक ट्रांसपोर्टर के माध्यम से डीसीएम बुक कर अनार की खेप चढ़घई थी। करीब तीन लाख रुपये कीमत के अनार सिकरीगंज पहुंचाया जाना था। डीसीएम गुजरात से रवाना होकर गोरखपुर की ओर आ रहा था। व्यापारी को इसकी जानकारी मिलती रही कि वाहन रास्ते में है। बताया जा रहा है कि डीसीएम ने तेनुआ टोल प्लाजा पार किया और इसके बाद अचानक चालक से संपर्क टूट गया। व्यापारी ने चालक के मोबाइल पर संपर्क करने के साथ ही ट्रांसपोर्टर से भी डीसीएम और फल की खेप के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों के साक्षात्कार की तिथियां घोषित

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत वर्ष 2026–27 में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों के साक्षात्कार की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं।जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से ट्रेडवार कार्यक्रम जारी किया गया है।कार्यक्रम के अनुसार दर्जी ट्रेड के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 5, 7, 8 एवं 9 सितंबर को, जबकि हलवाई ट्रेड के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 10 एवं 11 सितंबर को होंगे। इसी क्रम में कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री एवं धोबी ट्रेड के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 14 सितंबर तथा बढ़ई, नाई एवं मोची ट्रेड के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 15 सितंबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे।सभी ट्रेड के साक्षात्कार कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, मदरबाजार, अयोध्या में प्रातः 11 बजे से शुरू होंगे।विभाग ने सभी लाभार्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने सभी मूल अभिलेखों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार साक्षात्कार में शामिल होकर लाभार्थी प्रशिक्षण प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई पूरी कर सकेंगे।

शाम ढलते ही शहर के कई इलाकों मे सक्रिय हो जाते है अराजक तत्व

अयोध्या।इस समय केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति अभियान सहित कई अभियान चला रही है।महिला हेल्प डेस्क,एंटी रोमियो टीम, डायल–112 और पुलिस की अन्य व्यवस्थाओं के जरिए सुरक्षित वातावरण देने का दावा भी किया जाता है।इसके बावजूद अयोध्या शहर के कई चौक, कोचिंग, कालेज,हास्टल के अलावा प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर शाम ढलते ही अराजक तत्व सक्रियता हो जाते है।जिसके चलते शहर पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।देखा जाये तो शहर के गुलाबबाड़ी मैदान, रीडगंज तिराहा, रीडगंज ओवरब्रिज, जेल के पीछे, पुष्पराज चौराहा,सिविल लाइन चौराहा,रिकाबगंज चौराहा, राठहवेली,लालबाग रेलवे क्रॉसिंग,मोदहा चौराहा, देवकाली बाईपास, देवकाली तिराहा, बेनीगंज,सहित कई स्थानों पर शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है।देखा जाए शहर के गुलाबबाड़ी,रीडगंज तिराहा,रीडगंज ओवरब्रिज,गुलाब बाड़ी मैदान,नाका सहित कई प्रमुख ऐसे स्थान है जहां पर दिनदहाड़े और देर रात चेन स्नेचिंग,छिनैती सहित अन्य प्रमुख आपराधिक घटनाएं घट रही हैं।यह तो एक उदाहरण है।स्थानीय लोगों के मुताबिक,कुछ स्थानों पर शाम होते ही जुआ, सट्टा और नशे जैसी गतिविधियों में लोगों के जुटने की स्थिति दिखाई देती है।इन रास्तों से गुजरने वाली महिलाओं और छात्राओं को कई बार फब्तियों और छेड़खानी जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ने की शिकायतें भी रहती हैं।बाहर से आने वाले राहगीरों के साथ छीना–झपटी और लूट जैसी घटनाओं की आशंका भी लोगों को परेशान करती है। इस संबंध में सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी का कहना है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह गंभीर है।मिशन शक्ति सहित विभिन्न अभियानों के माध्यम से लगातार सुरक्षा एवं जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी महिला की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।बताया कि महिलाओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

नई जिला जेल का निर्माण जल्द, 73.21 करोड़ जारी

भदोही, (संवाददाता)। मूंसीलाटपुर में नई जिला जेल का निर्माण जल्दी ही शुरू होगा। शासन ने 209.18 करोड़ की लागत से प्रस्तावित कारागार के लिए 73 करोड़ जारी कर दिया है। 60 एकड़ में प्रस्तावित कारागार में कुल 574 बंदी क्षमता होगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू किया जाएगा। काशी नरेश विश्वविद्यालय के पास अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बने उप कारागार को कुछ साल पहले जिला कारागार का दर्जा दिया गया, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ीं। 114 बंदियों की क्षमता वाले इस कारागार में 350 से अधिक बंदी रहते हैं। जिला कारागार के निर्माण की कवायद बीते एक दशक से चल रही है। पांच साल पहले उस समय तेजी आई, जब बंदियों की अधिक संख्या को देखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी और डिप्टी जेलर ने प्रयास किया। पर्याप्त जमीन की उपलब्धता को देखते मूंसीलाटपुर में कारागार के निर्माण का निर्णय लिया गया। नवंबर 2019 में तहसील प्रशासन ने ग्राम समाज की 45 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी थी। जमीन पर्याप्त नहीं होने के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर बाद में किसानों से जमीन ली जाने लगी। साल 2020 और 2021 में कोरोना के कारण काम रुक गया। साल 2022 में परियोजना ने फिर रफ्तार पकड़ी। 60 एकड़ भूमि का बैनामा होते ही शासन ने धनराशि जारी कर दी। जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि नए जेल के निर्माण के लिए शासन स्तर से प्रथम किस्त के रूप में 73.21 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि नई जिला जेल आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था से लैस होगी।

छेड़खानी के मामले में अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

भदोही, (संवाददाता)। नाबालिग से छेड़खानी और धमकी देने में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। पीड़िता की मां ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बताया कि नौ सितंबर 2025 को 15 वर्षीय बेटी स्कूल जा रही थी। शिवा गौतम बेटी को रास्ते में रोककर साइकिल पर बैठने के लिए कहने लगा। आरोप है कि 12 नवंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे बेटी घर लौट रही थी। शिवा ने पीछे से उसे पकड़ लिया। शोर मचाने पर उसका भाई मौके पर पहुंचा। इस पर आरोपी धमकी देते हुए चला गया। कुछ देर बाद शिवा व जितई, जैकी, संचन गौतम और राजमनि लाठी–डंडे लेकर उनके घर पहुंच गए। दरवाजा बंद होने पर आरोपितों ने खिड़की और दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।